

>

Title: Regarding need to provide reservation in jobs in private sector.

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वॉ में बहुत तेजी के साथ सरकारी उपक्रमों का विनिवेश हुआ। उसमें न सिर्फ वे उपक्रम बेचे गये, जो घाटे में थे, बल्कि मुनाफे के सरकारी उपक्रमों का भी विनिवेश हुआ। उस समय यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि उसके बाद उपक्रम में काम करने वाले जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके भविय का क्या होगा। यह जो यू.पी.ए. की गवर्नमेंट है, इसकी प्रतिबद्धता थी कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी आरक्षण देंगे। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ तो उसमें भी इस संकल्प को व्यक्त किया गया था। जब कभी भी इस सदन में चर्चा हुई तो सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाया जायेगा। श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया गया। मुझे नहीं मालूम कि उस समूह ने कितना आगे चलने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, संदेश यह जा रहा है कि जो निजी क्षेत्र के बड़े घराने हैं, उनके दबाव में यह सरकार मन्द गति से काम कर रही है।

हम आपके मार्फत जरूर जानना चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल सरकार कब तक लायेगी और उसको लागू करने का काम कब तक करेगी? हम आपका संरक्षण चाहते हैं।[R25]

महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। सरकार बताए कि यह बिल कब आएगा और इसका क्या भविय है? ... (व्यवधान) सरकार का जो कामन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें सरकार की प्रतिबद्धता थी। सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ... (व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं। सरकार बताए कि क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है? क्या कोई मर्यादा है कि सरकार कब तक यह बिल लाएगी?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Sumanji, your statement has already gone on record.

श्री रामजीलाल सुमन : यहां महावीर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, ... (व्यवधान) इनको जरूर इसका जवाब देना चाहिए। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You know, I cannot compel the hon. Minister. Now, please sit down.

श्री रामजीलाल सुमन : संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं। ... (व्यवधान) यह कब तक किया जाएगा? ... (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, we also associate ourselves with the issue raised by Shri Ramji Lal Suman.

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपनी चिट्ठी भेज दें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। सभी राजनीतिक दलों में इसके बारे में चर्चा हो रही है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं इनकी भावना से सरकार को अगवत कराऊंगा।

